



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ, 1946 (श०)

संख्या - 92 राँची, सोमवार,

17 फ़रवरी, 2025 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

-----

#### अधिसूचना

17 जनवरी, 2025

**संचिका संख्या- 4/ न्यायालय-1006/2014 का. 303--W.P.(S) No.- 454/2014- सदन**  
प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायलय, राँची द्वारा दिनांक-  
25.07.2019 को पारित नयायादेश के कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"Be that as it may, the case of the petitioner needs to be considered by the respondents in view of kalawadhi. The case of the petitioner was required to be considered three years earlier whereas the petitioners's case has been considered later on. Accordingly, the matter is remitted back to Respondent No.-2 who will take appropriate steps so that the case of the petitioner may be considered at an early date. The Respondent No.-2 will ensure that the case of the petitioner be placed before the ensuing D.P.C. for consideration on the promotional post with effect from the date the petitioner has prayed in the writ petition."

2. W.P. (S) No.- 454/2014- सदन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-25.07.2019 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में समीक्षोपरान्त विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची से परामर्श प्राप्त कर उक्त न्याय निर्णय के विरुद्ध LPA 778/2019 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम सदन प्रसाद दायर किया गया, जिसमें दिनांक-10.11.2022 को निम्न आदेश पारित हुआ :-

13. This Court, after considering the factual aspect in detail as above and after going through the order contained in the impugned order has found there from that there is no issue of writ petitioner having not eligible for consideration of promotion, rather only ground taken by way of objection on the part of the State authority that the Departmental Promotion Committee since has not convened its meeting and since the writ petitioner has retired, therefore, he cannot be considered for promotion to the higher post and taking the same contrary to the position of law conferring the public servant a right to be considered for promotion to be a fundamental right, in the circumstances, it is due to laches committed on the part of the State, the meeting of DPC could not be convened and as such, for wrong committed by the State, the writ petitioner cannot be denied from the chance of consideration for promotion,

The learned Single Judge if disposed of the writ petition while directing the respondents to consider the case of the writ petitioner by placing his case in the ensuing Departmental Promotion Committee, which according to our considered view, cannot be said to suffer from an error.

14. The said finding cannot be considered to be incorrect, for the reason that the writ petitioner cannot be denied from the right of consideration of promotion to the higher post, as per the ratio laid down by the Hon'ble Apex Court in Deepak Agarwal & Anr. Vrs. State of Uttar Pradesh & Ors. (Supra) and Subodh Kumar and Others Vrs. Commissioner of Police and Others (Supra).

15. This Court, therefore, is of the view that the order passed by the learned Single Judge suffers from no error.

16. In the result, the instant appeal fails and is, dismissed.

17. In consequent to dismissal of this appeal, I.A. No. 10729 of 2019 stands disposed of."

3. W.P.(S) No. 454/2014 सदन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-25.07.2019 को पारित न्यायादेश तथा L.P.A. No. 778/2019, झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम सदन प्रसाद में दिनांक-10.11.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में तथा दिनांक-22.05.2024 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-3664 दिनांक-30.05.2024 द्वारा याचिकाकर्ता श्री सदन प्रसाद, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनके द्वारा याचित तिथि दिनांक 05.06.2013 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की गई।

4. W.P.(S) No. 454/2014 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु याचिकाकर्ता श्री सदन प्रसाद के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में Contempt (C) No. 818/2022, सदन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-18.10.2024 को उक्त अवमाननावाद की सुनवाई करते हुए निम्नवत् निदेश दिया गया:-

It has been pointed out in course of the argument that the persons who have not approached the High Court, they have been provided with benefit of Kalawadhi along with monetary benefits, however, in the case of the petitioner, only notionally it has been provided. It was pointed out that it has been done because the petitioner has approached the High Court by way of filing the writ petition. It was further pointed out that the writ Court's order is confirmed by the Division Bench in L.P.A. No.778 of 2019 and the notification dated 17.8.2023 with regard to other persons have been brought on record by the learned counsel for the petitioner in supplementary affidavit contained in Annexure-4.

2. In view of above, by way of last indulgence, further time is granted to the Opposite parties to comply the order.

3. Let this matter appear on 22.11.2024.

5. अतः Contempt (C) No. 818/2022 में दिनांक-18.10.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री सदन प्रसाद, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची सम्प्रति-सेवानिवृत्त को प्रशाखा पदाधिकारी (पी. बी.- II, पे. बैंड रु० 9300-34800/-, ग्रेड पे. रु० 4800, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-8) कोटि से अवर सचिव (पी०बी०-III, पे० बैंड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) कोटि के पद पर उनके द्वारा याचित तिथि दिनांक-05.06.2013 के भूतलक्षी प्रभाव से आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान किया जाता है।

6. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74, झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2074/वि(2) दिनांक 04.04.1985 जो भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति व आर्थिक लाभ नहीं दिये जाने के प्रावधान से सम्बन्धित है एवं अन्य संगत परिपत्रों को विशेष परिस्थिति में शिथिल करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संलेख ज्ञापांक-37 दिनांक-03.01.2025 में सन्निहित प्रस्ताव पर दिनांक-07.01.2025 को मंत्रिपरिषद् की बैठक की मद संख्या-05 के रूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है ।

7. श्री सदन प्रसाद को अवर सचिव के पद पर दी गई वैचारिक प्रोन्नति से सम्बन्धित विभागीय अधिसूचना संख्या-3664 दिनांक-30.05.2024 को इस हद तक संशोधित समझा जाए ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अनल प्रतीक मिंज,**  
सरकार के उप सचिव ।

-----